



साँवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना

प्रलिस के लयि:

सरकारी प्रतभूति (जीएस) अधनियम, 2006, आरबीआई, आयकर अधनियम, 1961।

मेन्स के लयि:

साँवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना, इसके फायदे और नुकसान।

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) के परामर्श से 2022-23 के लयि साँवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) कश्तों में जारी करेगी।

- SGB में नविश [कोवडि-प्रभावति वर्षों](#) के दौरान तेजी से बढ़ा क्योकनविशकों ने 2020-21 और 2021-22 के साथ इक्वटी बाज़ारों में अस्थरिता के बीच सुरकषति वकिल्पों की तलाश की, जो नवंबर 2015 में योजना की स्थापना के बाद से बॉण्ड की कुल बकिरी का लगभग 75% हसिसा था।

साँवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना:

- **शुरुआत:**
 - सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हसिसे (जसिका उपयोग स्वर्ण की खरीद के लयि कयिा जाता है) को वत्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से नवंबर, 2015 में साँवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond) योजना की शुरुआत की थी।
- **नरिगमन:**
 - गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड सरकारी प्रतभूति (GS) अधनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी कयिा जाते हैं।
 - ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा जारी कयिा जाते हैं।
 - बॉण्ड की बकिरी वाणजियकि बैंकों, स्टॉक होल्डगि कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामति डाकघरों (जनिहें अधसूचति कयिा जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के ज़रयि या तो सीधे अथवा एजेंटों के माध्यम से की जाती है।
- **पात्रता:** इन बॉण्डों की बकिरी नवासी व्यक्तयिों, हद्दु अवभाजति परिवारों (HUFs), न्यासों/ट्रस्ट, वशिवदियालयों और धर्मारथ संस्थानों तक ही सीमति है।
- **वशिषताएँ:**
 - **वमिचन मूल्य:** गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड की कीमत इंडिया बुलयिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (India Bullion and Jewellers Association- IBJA) द्वारा 999 शुद्धता वाले सोने (24 कैरट) के लयि प्रकाशति मूल्य पर आधारति होती है।
 - **नविश सीमा:** गोल्ड बॉण्ड एक ग्राम यूनटि के गुणकों में खरीदे जा सकते हैं जसिमें वभिन्नि नविशकों के लयि एक नश्चति सीमा नरिधारति होती है।
 - खुदरा (व्यक्तगित) तथा हद्दु अवभाजति परिवारों (Hindu Undivided Families- HUFs) के लयि खरीद की अधिकतम सीमा 4 कलोग्राम है। ट्रस्ट एवं इसी तरह के नकियायों के लयि प्रतवित्त वर्ष 20 कलोग्राम की अधिकतम सीमा लागू होती है।
 - संयुक्त धारति के मामले में 4 कलोग्राम की नविश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होती है।
 - न्यूनतम स्वीकार्य नविश सीमा 1 ग्राम सोना है।
 - **अवधि:** इन बॉण्डों की परपिकवता अवधि 8 वर्ष होती है तथा 5 वर्ष के बाद इस नविश से बाहर नकिलने का वकिल्प उपलब्ध होता है।
 - **ब्याज दर:** नविशकों को प्रतविरष 2.5 प्रतशित की नश्चति ब्याज दर लागू होती है, जो छह माह पर देय होती है।
 - गोल्ड बॉण्ड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर कर/टैक्स आयकर अधनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार अदा करना होगा।
- **लाभ:**
 - ऋण के लयि बॉण्ड का उपयोग संपारश्वकि (जमानत या गारंटी) के रूप में कयिा जा सकता है।
 - कसि भी व्यक्त को साँवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) के वमिचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दयिा गया है।

- वमिौचन (Redemption) का तात्पर्य एक जारीकर्त्ता द्वारा परपिक्वता पर या उससे पहले बॉण्ड की पुनर्खरीद के कार्य से है ।
- पूंजीगत लाभ (Capital Gain) स्टॉक, बॉण्ड या अचल संपत्तिका जैसी संपत्तिका बिक्री पर अर्जति लाभ है । यह तब प्राप्त होता है जब कसिी संपत्तिका वकिरय मूल्य उसके करय मूल्य से अधिक हो जाता है ।

▪ **SGB में नविश के नुकसान:**

- यह भौतिक स्वर्ण (जसै तुरंत बेचा जा सकता है) के वपिरीत एक दीर्घकालिक नविश है ।
- सॉवरेन गोलड बॉण्ड एकसचेंज पर सूचीबद्ध होते हैं लेकिन इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता , इसलिये परपिक्वता से पहले बाहर नकिलना मुश्कल होगा ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्र. सरकार की 'सॉवरेन गोलड बॉण्ड योजना' और 'स्वर्ण मुद्रीकरण योजना' का लक्ष्य/उद्देश्य क्या है/हैं? (2016)

1. भारतीय परवारिों के पास बेकार पड़े सोने को अर्थव्यवस्था में लाना ।
2. स्वर्ण और आभूषण क्षेत्र में प्रत्यक्ष वदिशी नविश को बढ़ावा देना ।
3. सोने के आयात पर भारत की नरिभरता को कम करना ।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (A) केवल 1
 (B) केवल 2 और 3
 (C) केवल 1 और 3
 (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

व्याख्या:

- सॉवरेन गोलड बॉण्ड स्कीम और गोलड मोनेटाइजेशन स्कीम को सरकार ने वर्ष 2015 में लॉन्च किया था ।
- इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- देश में घरों और संस्थानों के पास रखे सोने को जुटाना । अतः कथन 1 सही है । बैंकों से ऋण पर कच्चे माल के रूप में सोना उपलब्ध कराकर देश में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना ।
- घरेलू मांग को पूरा करने के लिये समय के साथ सोने के आयात पर नरिभरता कम करने में सक्षम होना । अतः कथन 3 सही है ।
- इन योजनाओं का उद्देश्य सोना और आभूषण क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देना नहीं है । अतः कथन 2 सही नहीं है । अतः विकल्प (C) सही उत्तर है ।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया